93वीं विज्ञान कांग्रेस

के अवसर पर संबोधन

मुख्य विषय

एकीकृत ग्रामीण विकास - विज्ञान और प्रौद्योगिकी

श्री कपिल सिब्बल
माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं
महासागर विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

द्वारा

उद्‌घाटन भाषण

दिनांक 3 जनवरी, 2006

स्थानः आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय,
राजेन्द्र नगर, हैदराबाद

डा. मनमोहन सिंह जी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री, श्री सुशील कुमार शिन्दे, आंध्र प्रदेश के महामहिम राज्यपाल, डा. वाई एस. राजशेखर रेड्डी, माननीय मुख्य मंत्री, आंध्र प्रदेश, डा. एस. रघु वर्द्धन रेड्डी, कुलपति, आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय एवं अध्यक्ष, संयोजन समिति, प्रो. वी.एस. राममूर्ति, सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, प्रो. आई.वी. सुब्बाराव, जनरल प्रेसीडेंट, 93वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, प्रो. सी.एन.आर. राव, भारतीय विज्ञान पुरस्कार प्राप्तकर्ता, वैज्ञानिक समुदाय के प्रतिष्ठित सदस्य, देवियो और सज्जनों,

1. हैदराबाद की इस सुन्दर नगरी में इस समय आयोजित विज्ञान कांग्रेस में दूसरी बार भाग लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वास्तव में आज यह काफी विशेष अवसर है। हम आधुनिकता की ओर हमारे राष्ट्र के बढ़ते कदमों में वैज्ञानिक समुदाय के योगदानों को ही नहीं मना रहे हैं बल्कि यह समारोह इस रूप में अपना विशेष स्थान रखता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री भारत के एक महान सपूत, प्रो. सी.एन.आर. राव को पहला भारतीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं।

2. यह कांग्रेस जिसका मुख्य विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से एकीकृत ग्रामीण विकास है, हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का जायजा लेने के लिए हमें एक अवसर प्रदान करती है और भविष्य के लिए एक कार्य योजना भी प्रदर्शित करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 जुलाई, 2005 को सी.एस.आई.आर. सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में अपने सम्बोधन में यह दृष्टिकोण स्पष्ट किया था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को किस प्रकार भविष्य की चुनौतियों का सामना करना चाहिए, उन्होंने कहा था "हमारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रणाली तभी अपनी निर्णायक भूमिका अदा कर सकती है जब यह कुछ ही विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों का नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों के कल्याण को आगे बढाये। इसको कुछ ही चुने गये व्यक्तियों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए सम्पत्ति सृजित करने की बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। एक ऐसा विषय जिसे मैं तहेदिल से महसूस करता हूँ वह है 'गरीबों और साधनविहीनों के लिए प्रौद्योगिकी कार्य करना'। दूसरे शब्दों में हम ऐसी प्रौद्योगिकियाँ विकसित कर सकते हैं जो गरीबी दूर करेंगी, रोजगार उत्पन्न करेंगी, गरीबी के बोझ को दूर करेंगी और जीवन की सम्पूर्ण गुणवत्ता में सुधार लायेंगी।"

यह एक मात्र संयोग नहीं है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर जनवरी, 1947 में विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय था "राष्ट्र की सेवा में विज्ञान"। हमारा उद्देश्य स्पष्ट

है। राष्ट्र की सेवा के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आम आदमी के जीवन को सुधारना चाहिए।

3. विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपने प्रबल विश्वास के लिए हम पंडित जी का धन्यवाद करते हैं और परवर्ती राजनैतिक संरक्षण को भी धन्यवाद देते हैं जिसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को यह सुविधाएं दी, स्वतंत्रता के समय यह उच्च गुणवत्ता का केवल एक छोटा सा विज्ञान था और आधुनिक प्रौद्योगिकी का उसमें लगभग अभाव था, परन्तु राष्ट्र ने पिछले छः दशकों में काफी प्रगति की है। आज हम एक विशाल, विविधीकृत विज्ञान और प्रौद्योगिकी संरचना की बात गर्व के साथ कर सकते हैं जिसके अंतर्गत अनेक विषय शामिल हो गये हैं।

4. अंतरिक्ष विज्ञान में भारत के पास अपने उपग्रह तैयार करने और उनके प्रक्षेपण की क्षमता है और दूरसंवेदन के लिए सात उपग्रह विश्व में ऐसे सबसे बड़े उपग्रह समूह मे से एक हैं। हमारे परमाणु कार्यक्रम ने, जिसे शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए बनाया गया है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए विशाल रियक्टरों के लिए कच्ची सामग्री से लेकर उनके अभिकल्पन, विनिर्माण और प्रचालन तक की सम्पूर्ण प्रौद्योगिकी स्वदेशी रूप से विकसित की है। रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में हमारे पास अपने लड़ाकू विमान और आधुनिकतम मिसाइलें तैयार करने की क्षमता है। कृषि के क्षेत्र में हम हर वर्ष खाद्यान्नों का आयात करते थे परन्तु अब खाद्यान्नों का निर्यात करने वाले देशों में हैं और हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न का भण्डार है। महासागर अनुसंधान में हमें समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अंतर्गत 'अग्रणी निवेशक' का दर्जा प्राप्त करने वाले पहले राष्ट्र का सम्मान मिला है और हमने अंटार्कटिका में दो स्टेशन स्थापित कर लिये हैं। हमने विगत तीन दशकों में जैव प्रौद्योगिकी में जो निवेश किये थे वह फलीभूत होने शुरू हो गये हैं। आज हम विश्व में वैक्सीनों के बड़े उत्पादकों में से एक हैं और प्लांट बायो टेक्नोलोजी में हमने आनुवांशिकी रूप से परिष्कृत कपास विकसित किया है। अनेक आनुवांशिकी रूप से परिष्कृत खाद्य फसलों का विकास कार्य चल रहा है जो भारत को निरन्तर हरित क्रांति की ओर ले जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र में भारत के फर्मास्यूटिकल उद्योग की विजय अनुकरणीय है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अपनी अत्यधिक प्रगति के कारण भारतीय फर्मास्यूटिकल उद्योग अपने देश की आवश्यक औषधियों के 99% का उत्पादन करता है और अत्यधिक प्रतियोगी भूमंडलीय परिदृश्य में यह अपने उत्पादन का 40 % निर्यात करता है।

परन्तु इस सफलता की कहानी के पीछे एक दूसरा भी पक्ष है।

5. हमने जिन विकासात्मक माडलों को विश्व में उतारा है उन्होंने 'वंचित' लोगों की एक दुनिया को उत्पन्न किया है और असमानता का एक वातावरण दिया है। विश्व की सर्वाधिक धनी एक प्रतिशत आबादी की आय सबसे गरीब 75 प्रतिशत व्यक्तियों की आय के बराबर है। भारत में भी यह तस्वीर इससे भिन्न नहीं है। हम एक ऐसे भारत में रहते हैं जहां करोड़ों बच्चे परिहार्य भुखमरी, बीमारी और कष्टों से पीड़ित हैं। ग्रामीण गरीबी की सीमा तो बहुत ही निराशाजनक है और यह दुखद स्थिति परिहार्य अभावों की ही नहीं है बल्कि यह उनके साथ विद्यमान है जो ग्रामीण गरीबों की दशा के प्रति उदासीन हैं और जिसकी उनको कोई परवाह नहीं है। यह संख्या बहुत ही आश्चर्यजनक है और हमें इसपर शीघ्र कार्रवाई की जरूरत है।

6. लेकिन यह कार्य किसे करना चाहिए ? प्रायः यह कहा जाता है कि अपनी स्वयं मदद करना सहायता का सबसे अच्छा रूप है। ग्रामीण गरीबों को अपनी सहायता स्वयं करनी चाहिए। लेकिन प्रायः वे ऐसा नहीं कर पाते। उन्हें ऐसा करने में समर्थ और सशक्त बनाने की पहल करने की जिम्मेदारी हम अमिजात्य तथा सुविधा सम्पन्न लोगों पर है, जिनके पास काफी अधिक अधिकार, जानकारी और संसाधन हैं।

7. प्रजातंत्र और स्वतंत्रता में जानकारी उत्पन्न करना, उसकी पहुंच, आमेलन और सामाजिक उपयोग और स्वतंत्रता की समानतावादी भागीदारी शामिल है। भारत में विकास की भिन्न - भिन्न मात्राओं के कारण अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों के पास इस प्रक्रिया में भागीदारी के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है। और यह कार्य तब और कठिन हो जाता है जब जानकारी का उपयोग वर्चस्व के लिए एक यंत्र के रूप में किया जाता है न कि " खाइयों को पाटने" के लिए। जानकारी रखने वालों की संख्या बहुत कम है और " वंचित लोगों" में से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जो जानकारी के लाभों से वंचित है।

8. ग्रामीण विकास को पारम्परिक रूप से कृषि के साथ जोड़ा जाता है लेकिन पिछले कई वर्षों में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान में काफी कमी आई है - जो स्वतंत्रता के समय सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 55% से वर्तमान में घटकर लगभग 20% हो गया है। ग्रामीण समाज और कृषि संबंध संक्रमण के दौरे में है - पहले की स्थिति में कृषि प्रमुख प्रेरक बल था जबकि नई स्थिति में ग्रामीण विकास पर गैर कृषि कारकों के प्रभाव में वृद्धि हो रही है। समेकित ग्रामीण विकास इस प्रकार

विकास नीति संरचना की एक नई समझ को परिलक्षित करती है --- जिसमें विभिन्न कारकों की जटिल बहुआयामी पारस्परिकता शामिल है जिसका विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी एक कारक है। जिस बात की आवश्यकता है वह है एक राष्ट्रीय नवोन्मेष प्रणाली के माध्यम से भागीदारी की नई एवं सृजनशील नीतियों, कार्यनीतियों एवं माडलों का निर्माण जिसके द्वारा ग्रामीण समाज को समृद्धि की दिशा में भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण रूप से जोड़ा जा सके।

9. इस परिदृश्य में सरकार की भूमिका केवल सार्वजनिक निधियां स्वीकृत्त करने और नीतियां तैयार करने तथा उन्हें शीर्ष स्तर पर कार्यान्वित करने की ही नहीं है बल्कि नीतियों, नियोजन के समन्वित निर्माण और उनके कार्यान्वयन के लिए सभी कारकों की भागीदारी को बढ़ावा देना इससे भी महत्वपूर्ण है। यह कहीं अधिक सक्रिय भूमिका है जिसके लिए ग्रामीण कार्यनीतियों को बढ़ावा देने, उन पर विचार विमर्श करने और मानीटर करने तथा परिणामों के मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए संस्थानिक सुदृढ़ता की आवश्यकता है।

10. इन कार्यनीतियों के विकास एवं कार्यान्वयन और परियोजनाओं के संचालन के मार्ग में नवोन्मेष हेतु एक और बाधा हैः वह है हमारे सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित आर एण्ड डी संस्थानों की अपर्याप्तता और नीतियों के निष्पादन एवं कार्यान्वयन और ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने की कम क्षमता। इस प्रकार इन संस्थानों के सार्वजनिक प्रबंधन के माडलों को ऐसे प्रतिमानात्मक रूप से बदलना समय की मांग है जिससे वह इस मांग को प्रभावपूर्ण और कारगर रूप से पूरा कर सके।

11. हमारे वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विदों का व्यावसायिक स्थिति भी अवबोधन और विषमता युक्त प्राथमिकताओं के पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। इस प्रकार की मानसिकता शहरी, औद्योगिक, "उच्च" प्रौद्योगिकी, पूंजी प्रधान, शीतोष्ण जलवायु के लिए उपयुक्त, तथा बाजारीकृत एवं आयातित चीजों पर ध्यान देती है; जबकि ग्रामीण, कृषि जन्य, "निम्न" प्रौद्योगिकी, श्रम प्रधान, उष्ण देशीय जलवायु के लिए उपयुक्त, घरेलू रूप से पाए जाने वाले और स्थानीय रूप से उपभोज्य वस्तुओं की उपेक्षा की जाती है। ऐसा सर्वत्र देखा जा रहा है कि जानकारी और सम्मान की राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय प्रणाली, उनसे जुड़े पुरस्कार एवं प्रोत्साहन इन व्यावसायिकों को शहरी तथा अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों से दूर ले जाती है।

12. हमारे इसी पूर्वाग्रह को दर्शाने वाला एक लक्षण है - अनुसंधान और विकास के लिए संसाधनों का आबंटन। यह कुछ हद तक उस क्षेत्र में प्रणाली द्वारा दिए जाने वाले महत्व का एक मानदण्ड है। व्यापक तौर पर अनुसंधान और विकास व्यय औद्योगिक एवं सामरिक क्रियाकलापों पर संकेन्द्रित है। केन्द्र सरकार के अनुसंधान और विकास बजट का 50% से अधिक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सामरिक क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया जाता है। इन राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास संसाधनों का केवल एक छोटा सा भाग यदि लाखों ग्रामीण लोगों की गरीबी कम करने की ओर मोड़ दिया जाए तो यह राष्ट्र के लिए काफी लाभप्रद होगा।

13. एक अन्य कारक जो हमारे ग्रामीण भाइयों को प्रभावित कर रहा है वह है भूमण्डलीकरण। राष्ट्रीय अवरोधों को हटाना बड़ी आर्थिक शक्तियों का एक प्रयास है ताकि वे स्वयं को थोप सके और अपने हितों का स्वतंत्र रूप से प्रसार कर सकें। नए भूमण्डलीय प्रतिमान, विश्व बाजार को नियंत्रित करने के प्रयासों में बड़े बहु राष्ट्रिकों के वर्चस्व संबंधी हितों का संरक्षण करते हैं। डब्ल्यू टी ओ के परिणाम स्वरूप भारतीय किसान घटी हुई वैश्विक कीमतों के कारण अपने कृषि उत्पादों के निर्यात पर लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में असमर्थ हैं। प्रौद्योगिकी मिशन के प्रयासों के कारण तिलहन उत्पादन में हमारे द्वारा अर्जित लगभग आत्मनिर्भरता की स्थिति सस्ते वनस्पति तेल आयात पर निर्भरता के कारण अव्यवस्थित हो गई। 1996 - 97 और 2003 - 04 के बीच भारत में कृषि आयात में परिमाण में 375% और मूल्य के संबंध में 300 % की वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय है कि कृषि गत जी डी पी के अनुपात में आयात के मूल्य में भी उसी अवधि के दौरान 3% से कम की तुलना में 4.34 % की वृद्धि हुई है। लेकिन हम अपने किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने हेतु यथा संभव प्रयास कर रहे हैं जैसाकि हाल ही में हांगकांग में सम्पन्न डब्ल्यू टी ओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में प्रदर्शित हुआ है। इस सम्मेलन में भारत के नेतृत्व वाली भूमिका से "खाद्य सुरक्षा" सुनिश्चित करने और विश्व स्तरीय कृषि बाजारों की अनुचित नीतियों से अपने किसानों का संरक्षण करने हेतु कार्यतंत्र तैयार करने में मदद मिली है।

14. सरकार ग्रामीण गरीबों के हितों की रक्षा करने हेतु हरसंभव प्रयास कर रही है। हमारे ग्रामीण लोगों की स्थिति में सुधार लाने हेतु कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अपने किसानों को सशक्त बनाने के लिए हमने पहले ही दिशा निर्देश तैयार कर लिए हैं। जनवरी 2004 में कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया किसानों के लिए काल सेंटर ऐसा ही छोटा सा प्रयास है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बुनियादी दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के मिश्रण का उपयोग कर कृषक समुदाय के बीच पहुंचना है। हमारे

कृषि विश्वविद्यालयों के युवा स्नातकों को देश भर के 11 नगरों में स्थित कॉल सेंटरों में तैनात किया गया है जो देश भर के अशिक्षित तथा अल्पशिक्षित किसानों को निशुल्क नम्बर पर फसल उत्पादन, फसल संरक्षण बागवानी, पशुपालन, कृषि और विपणन से संबंधित जानकारी 8 भाषाओं में उपलब्ध कराते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे किसानों ने इस कार्यक्रम का लाभ उठाने में उल्लेखनीय सूझबुझ दिखाई है।

15. भारतीय व्यापार भी ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे लोगों तक "पहुंचने और उन्हें अधिकारिता देने" में तेज रहा है । हमारे पास एच0एल0एल0 I - शक्ति कियोस्क हैं जिन्हें प्रारम्भ में आंध्रप्रदेश सरकार के राजीव गांधी इण्टरनेट ग्राम कार्यक्रम के साथ प्रारम्भ किया गया था । इनसे आय का उपार्जन करने की क्षमताओं का सृजन करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा विहीन महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने में सहायता मिलती है। आज इस कार्यक्रम का विस्तार 11 राज्यों के 20,000 गांवों में हो चुका है। हमारे पास आई0टी0सी0, ई-चौपाल भी है जिनका उद्देश्य हमारे उन किसानों को खेती और व्यवसाय सम्बंधी जानकारी प्रदान कर उन्हें समर्थ बनाना है जो छः राज्यों के 20,000 गाँवों में 4,000 चौपालों में रहते हैं। किन्तु अभी काफी कुछ करने की आवश्यकता है ।

16. मैं एकीकृत ग्रामीण विकास के लिए अपेक्षाकृत अधिक कारगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लाभों को पहुंचा सकने वाले तरीकों को आपके विचार और व्यापक विचार - विमर्श हेतु रखना चाहूँगा । मुझे विश्वास है कि हम निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श कर सकते हैं :-

- ग्रामीण क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मांग को बढ़ावा देना और इसे बढ़ाना ।
- जानकारी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समावेशन और उपयोग के लिए ग्रामीण समाज के उत्पादक और सार्वजनिक क्षेत्रों की क्षमता को मजबूत बनाना ।
- ग्रामीण समाज के सामाजिक और उत्पादक क्षेत्रों के नेटवर्कों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ संघटित करना ।
- ग्रामीण समाज की समस्याओं का समाधान करने के लिए वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को प्रेरित और जागृत करना ।
- ग्रामीण विकास की समस्याओं का समाधान करने के लिए जनता द्वारा निधिकरण की गयी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक संस्थाओं की प्राथमिकताओं और कार्यक्रमों में संशोधन करना ।

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए संसाधन आधार बढ़ाना जिससे ग्रामीण समाज की समस्याओं का निराकरण होता है ।

17. मेरा ध्यान बार-बार जनवरी, 1947 भारतीय विज्ञान कांग्रेस की ओर चला जाता है जब राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवियों ने सामाजिक भलाई के लिए राजनीति को अपनाया । मुझे पता है, आज हमारे राष्ट्र का नेतृत्व एक पेशेवर अर्थशास्त्री डा0 मनमोहन सिंह क्यों कर रहें हैं । शायद वे उसी दिशा में सोचते हैं जिसमें पं0 नेहरू सोचते थे और मैं उसे यहां दे रहा हूँ "आपमें से अधिकांश को यह पता है कि शताब्दी के अंतिम 25 वर्षों के दौरान और हाल में भारत में क्या - क्या होता रहा है । मेरे जैसा व्यक्ति जो सही तौर पर राजनीति का व्यक्ति नहीं है, को राजनीतिक कार्यकलाप में गहरी भूमिका निभानी है । मैने स्वयं से बराबर यह प्रश्न किया है कि ऐसा क्यों है, मुझे राजनीति में क्यों जाना चाहिए ? ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी क्षेत्र में विशेष रूप से विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करना तब तक संभव नहीं है जब तक आप बड़ी संख्या में मौजूद उन बाधाओं को दूर नहीं करते जो लोगों को उस तरह कार्य करने से रोकते हैं जिस तरह उन्हें करना चाहिए" ।

18. मैं पंडित जी की इस सलाह का स्मरण कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ जो उन्होंने 1947 में विज्ञान कांग्रेस में वैज्ञानिकों को दी थी ।

" मुझे आशा है कि विज्ञान कांग्रेस स्वयं को इस कार्य में समर्पित करेगा न कि वह केवल सरकार द्वारा कार्रवाई किये जाने की प्रतीक्षा करेगा । सरकारें अच्छी और बुरी हो सकती हैं किन्तु सरकारें सामान्य तौर पर अत्यन्त सुस्त होती हैं और एक मात्र चीज जो उस पर असर डालती है वह जनता का कुछ तत्काल विरोध जो उनके भविष्य को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अतः मुझे सरकार द्वारा कुछ कर सकने या न कर सकने के सहारे बैठे रहने को हतोत्साहित करना चाहिए"।

19. हमें जिसकी आवश्यकता है वह सरकार, वैज्ञानिक समुदाय, सिविल समाज और भारत के उद्यमियों के बीच साझेदारी है । एक ऐसी भागीदारी जो भारत को सेवा प्रदान करेगी और इस प्रक्रिया में हर भारतीय सेवा प्रदान करेंगे । भारत अभी परिपक्व नहीं है। हमारी आधी से अधिक आबादी जो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ की संयुक्त जनसंख्या से अधिक है, 25 की उम्र से कम है । हमारी शैक्षिक प्रणाली के व्यापक विस्तार से 10 मिलियन से अधिक विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत हैं । इससे अत्यन्त योग्य, कुशल और प्रतिभासम्पन्न युवाओं के एक फूलते-फलते समूह में वृद्धि हुई

है । चुनौती है कि हम अपने युवाओं को विकल्प की स्वतंत्रता दें, उनकी आंखों में भविष्य के सपने जगमगाएं और उनके लिए एक ऐसा परिवेश तैयार करें जिसमें उनकी बुद्धिमत्ता की पहचान हो । मुझे विश्वास है कि इस कांग्रेस के दौरान किये गये विचार-विमर्श उनके सपनों को साकार करने में लाभदायक साबित होंगे ।

20. आम आदमी की सेवा करने के लिए अपने अभियान के एक अंग के रूप में हम वर्ष 2006 में निम्नलिखित कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैः

i वर्ष 2006 के मध्य तक तमिलनाडु के तट के पास एक संयंत्र की स्थापना करना जिसमें प्रतिदिन एक मिलियन लीटर समुद्रीजल को पेयजल में बदला सके तथा इस वर्ष के अंत तक भारतीय तट पर ऐसे संयंत्र की संस्थापना करना जिससे प्रतिदिन 10 मिलियन लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके । यह विचार किया गया है कि पेयजल की लागत विश्व में किसी अन्य प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदत्त लागत से कम होगी ।

ii जलवायु, पर्यावरण, भू-उपयोग ओर महासागर संसाधनों से संबंधित विषयों पर हमारे ग्रामीण लोगों को विश्वस्तरीय जानकारी प्रदान करने में सहायता देने हेतु हमारे भूमि, महासागर और वातावरण कार्यक्रमों में अपने प्रयासों को एकीकृत करने के उद्देश्य से एक अर्थ कमीशन और अर्थ सिस्टम साइंस का गठन करना।

iii वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद को इस तरीके से रूपान्तरित करना कि सार्वजनिक -निजी भागीदारियों तथा जानकारी को समान आधार पर प्रतिष्ठापित करने के लिए साहसिक कदम उठाने हेतु इसे अपेक्षाकृत अधिक स्वायत्तता दी जा सके। यह रूपान्तरण वर्ष 2006 में पूरा कर लिया जायेगा और इससे वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी0एस0आई0आर0) एक कुशल, उत्तरदायी और कार्य - निष्पादनोमुखी संगठन बन जायेगा और राष्ट्र को बेहतर सेवा प्रदान करेगा ।

iv राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास नीति को तैयार करना और लागू करना। इससे अगले पांच वर्षों में पूर्ण रूप से जीवन विज्ञानों और जैव प्रौद्योगिकी हेतु 50 उत्कृष्ट केन्द्रों, 500 अनुसंधान पदों के एक राष्ट्रीय पूल का सृजन करने तथा पशु जैव प्रौद्योगिकी, सेरी - टेक्नोलॉजी तथा लोक स्वास्थ्य से संबंधित

प्रौद्योगिकी हेतु अनुसंधान के लिये संस्थाओं का गठन करना हमारे लिए सुगम हो जायेगा ।

v हमारे अनुसंधान संस्थानों की कार्यप्रणाली में आई0पी0आर0 को प्रमुख बनाने हेतु कानून बनाना। यह आविष्कारकों और अनुसंधान करने वाले संगठनों को उनके अभिनव प्रयासों का परिणाम प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा ।

vi निधि व्यवस्था बढ़ाकर विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान के एक स्वायत्त बोर्ड का गठन करना तथा भारत और विदेश में उच्च गुणवत्ता के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों और प्रयोगशालाओं में युवा शोधकर्त्ताओं हेतु 1,000 से अधिक वैज्ञानिक पदों का एक प्रारम्भिक पूल तैयार करना ।

vii उद्योग और अनुसंधान के बीच संयोजन का विकास करने के लिए क्षेत्रीय समूहों की स्थापना करना । ऐसे पहले अन्तरराष्ट्रीय समूह की स्थापना चण्डीगढ़ में की जायेगी जिसमें राष्ट्रीय नैनो-प्रौद्योगिकी संस्थान के भीतर नैनो जीवविज्ञान पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा ।